विचार बिन्दु

हमारी आनंदपूर्ण बदकारियाँ ही हमारी उत्पीड़क चाबुक बन जाती हैं। –शेक्सपियर

ट्रंप टैरिफ का भारत पर प्रभाव

डोनाल्ड ट्रंप ने जब 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, तभी यह स्पष्ट हो गया था कि उनके दूसरे कार्यकाल में कई बहुत दूरगामी प्रभाव वाले निर्णय लिए जाएंगे। इनमें से एक निर्णय जो कि अवैध प्रवासियों को अमेरिका से अपने-अपने देश में भेजने का था, उस पर तो कार्यवाही तत्काल ही प्रारंभ हो गई। इसका प्रभाव यह हुआ कि अमेरिका में रह रहे अवैध भारतीय प्रवासियो को हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़ कर अमेरिकी सेना के हवाई जहाज से भारत भेजा गया।

इसके बाद ट्रंप ने दूसरी बड़ी घोषणा 2 अप्रैल, 2025 को, रेसिप्रोकल टैरिफ (पारस्परिक आयात शुल्क) लगाने के संबंध में की । ट्रंप ने विश्व के 60 देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करने की घोषणा की।

पाठकों के लिए समझना आवश्यक है कि टैरिफ का मतलब आयात शुल्क है। एक देश से, दूसरे देश में जब भी कोई वस्तुएं निर्यात की जाती हैं तो आयात करने वाला देश, आयातित वस्तुओं पर आयात शुल्क लगाता है। इसे निर्धारित करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि आयात शुल्क इतना भी कम न हो कि देश में निर्मित होने वाली वस्तुओं से आयातित वस्तुएं बहुत सस्ती हो जाएं, ताकि स्थानीय उद्योग पर विपरीत प्रभाव न पड़े । यह इतना अधिक भी न हो कि आयातित वस्तु इतनी महंगी हो जाएं कि उन्हें कोई खरीद ही नहीं पाए । अमेरिका एक उपभोक्ता वादी देश है। अत: वहां कई देशों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बहुत खपत होती है। अमेरिका विश्व की एक नंबर की अर्थ व्यवस्था है और इसकी जी डी पी 27 ट्रिलियन डॉलर है, जो दुनिया की कुल जी डी पी का 26.11% है। इसकी तुलना में भारत की कुल जी डी पी 3.5 ट्रिलियन डॉलर है, जो वैश्विक जी डी पी का 3.36% है। प्रति व्यक्ति जी डी पी अमेरिका की 80700 डॉलर है जब कि भारत में यह केवल 2500 डॉलर है। अनेक देशों के उद्योग, उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के अमेरिका में उपभोग पर निर्भर हैं।

जहां तक भारत का संबंध है, भारत में अमेरिका से आयात होने वाली अधिकांश वस्तुओं पर 50 से 70% टैरिफ है। जबकि अमेरिका में भारत से जाने वाली अधिकांश वस्तुओं पर बहुत कम अर्थात 3 से 5% के बीच टैरिफ है। इस कारण अमरीकी उपभोक्ताओं को भारत में निर्मित वस्त्र, दवाइयां, रत्न आभूषण बहुत सस्ते उपलब्ध हो जाते हैं।

अब ट्रंप द्वारा टैरिफ में अचानक 26% वृद्धि करने से भारत में उत्पादित वस्तुओं की कीमत, अमेरिका में बहुत बढ़ जाएगी। यदि वहां के उपभोक्ता इतनी बड़ी क़ीमत पर क्रय नहीं करें, तो वहां के आयात कर्ता, भारत के निर्यातकों से वस्तुओं की कीमत कम करने के लिए कहेंगे। इसका मतलब यह होगा कि भारतीय उद्योग, यदि इतनी कम कीमत पर निर्यात करने में समर्थ नहीं होंगे, तो उन्हें अपनी उत्पादन क्षमता कम करनी होगी। परिणामस्वरूप, धीरे-धीरे उद्योग बंद होंगे और यहां काम करने वाले लोगों की संख्या में छंटनी होगी। इससे बड़ी मात्रा में बेरोजगारी बढ़ेगी और आर्थिक मंदी का दौर प्रारंभ होगा।

यह सर्वविदित तथ्य है कि वर्तमान समय, वैश्विक अंतर निर्भरता का है। वह जमाना अब नहीं रहा, जब कोई एक देश, पूरी दुनिया से कटकर अपने मन माने तौर से व्यापार कर सकता था । अपनी आर्थिक मजबूती का फायदा उठाते हुए, डोनाल्ड ट्रंप ने 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' के अपने वादे को पूरा करने की दृष्टि से 'रेसिप्रोकल टैरिफ' का कदम उठाया है। वर्तमान में, अमेरिका में आने वाली अधिकांश वस्तुओं पर बहुत कम आयात शुल्क था, जिसके कारण प्रतिस्पर्धी दरों पर विश्व के बहुत से देश, अमेरिका में काम आने वाली वस्तुओं का उत्पादन अपने देश में करके, निर्यात कर सकते थे। इसके कारण संबंधित देशों में उद्योग पनपते थे और वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता था।

2 अप्रैल 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व के विभिन्न देशों से आयात होने वाले वस्तुओं पर 10 से लेकर 50% तक टैरिफ लगाने का निर्णय लिया। भारत के लिए यह टैरिफ 26% है, जबकि चीन पर यह 34% है। टैरिफ की नई दरें 9 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएंगी।

जब से डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की है, तब से पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। सभी क्षेत्रों में इसका व्यापक असर दिखाई भी देने लगा है। यह आश्चर्य की बात है कि भारत में इस रेसिप्रोकल टैरिफ के निर्णय पर जितना जितनी चर्चा होनी चाहिए थी, वह अभी तक नहीं हुई है । इसी दृष्टि से यह लेख पाठकों के समक्ष स्थिति स्पष्ट करने हेतु लिखा गया है । भारत में चर्चा अधिक न होने का शायद एक कारण यह रहा कि हमारे यहां की सरकार जनता को हिंदू-मुसलमान के विवादों में ही उलझाती रही, चाहे वह औरंगजेब की कब्र को खोदने का मामला हो, छत्रपति शिवाजी का हो, या रामनवमी और ईद का हो, सड़कों पर नमाज पढ़ने का हो, अथवा वक्फ संशोधन कानून का हो । पूरा समय, लगभग सभी मीडिया चैनलों में इन्हीं विषयों पर निरंतर चर्चा होती रही है। इस कारण, जिस विषय से पूरे देश के आर्थिक भविष्य पर प्रभाव पड़ सकता है या रोजगार पर बहुत प्रभाव पड़ सकता है, वह विषय लगभग मीडिया से बाहर ही रहा है।

हम इस लेख में यह जानने का प्रयास करेंगे कि भारत पर ट्रंप की टैरिफ नीति का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

सबसे पहले यदि हम शेयर मार्केट की बात करें तो यह अभी से गिरना प्रारंभ हो गया है और जो शेयर मार्केट 2 अप्रैल को लगभग 77000 पर था वह घटकर तीन-चार दिन के अंदर ही 74000 तक आ गया है। अनुमान है कि शेयर मार्केट में गिरावट के कारण शेयर धारकों को लगभग 10 लाख करोड रुपए का नुकसान अभी तक हो चुका है।

अमेरिका द्वारा आयात शुल्क बढ़ाने के कारण अमेरिकी नागरिकों के लिए सभी चीज अत्यंत महंगी हो जाएंगी एवं उसके कारण अमेरिकी नागरिकों का तीव्र विरोध जब ट्रंप के विरुद्ध होगा, तब संभव है उन्हें अपना निर्णय बदलना पड़े। इस प्रकार का घोर विरोध प्रारंभ हो चुका है और पूरे देश में ट्रंप के विरुद्ध प्रदर्शन हो रहे हैं।

भारतीयों की सबसे अधिक रुचि सोने के भाव में रहती है और फिलहाल तो इसमें मामूली गिरावट देखी गई है, किंतु अंतत: अनुमान है कि इस नीति के कारण सोने के भाव प्रति 10 ग्राम के लिए लगभग एक लाख रुपए तक पहुंच सकता है, जो कि वर्तमान में 95000 रुपए है।

पाठकों के लिए यह जानना उपयुक्त होगा कि भारत के कुल निर्यात का लगभग 18% अमेरिका को होता है। इस निर्यात की कीमत लगभग 6 लाख 40 हजार करोड रुपए है। भारत द्वारा अमेरिका को निर्यात किए जाने वाली वस्तुओं में प्रमुख रत्न और आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, वस्त्र, फार्मास्यूटिकल उत्पाद, ऑटो पार्ट्स आदि हैं। इसके विपरीत, भारत में अमेरिका से होने वाला आयात लगभग 3.49 लाख करोड़ रुपए का है। इसका अर्थ यह है कि भारत से जितना निर्यात होता है, उससे लगभग तीन लाख करोड रुपए कम का आयात होता है। ट्रंप द्वारा फिलहाल सेमी कंडक्टर, एनर्जी उत्पाद, आई टी और फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र को इस रेसिप्रोकल टैरिफ के दायरे से बाहर रखा गया है। यदि इसे भी शामिल कर लिया जाता तो न केवल यहां के फार्मा सेक्टर पर बहुत प्रभाव पड़ता, अपितु अमेरिका में भी सारी दवाइयां बहुत महंगी हो जातीं।

अमेरिका ने भारत पर 26% का आयात शुल्क अथवा टैरिफ लगाया है जबकि चीन से आयात होने वाली वस्तुओं पर 34% का शुल्क लगाया है । वहीं, ब्राजील, इंग्लैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से होने वाली आयातित वस्तुओं पर 10% का ही शुल्क लगाया है। कई भारतीय नेता यह कहकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं कि चीन पर 34% का टैरिफ लगाया है जबकि भारत पर केवल 26% लगाया गया है। चीन और कुछ अन्य देशों ने जवाबी कार्यवाही करते हुए अमेरिका से आने वाली सामग्री पर टैरिफ बहुत बढ़ा दी है।

ट्रंप द्वारा टैरिफ बढ़ाने के पीछे यह तर्क दिया गया है कि जब बाहर से आने वाली वस्तुएं महंगी होंगी तब अमेरिका में इन वस्तुओं का अधिक उत्पादन होगा, जिसके फलस्वरूप अमेरिकी लोगों के लिए रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। ट्रंप के इस निर्णय के पीछे एक ही भावना दिखाई देती है - 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन'।

इसका वास्तविक प्रभाव तो 9 अप्रैल के बाद पड़ेगा किंतु इस घोषणा के बाद से ही बहुत उथल-पुथल और अनिश्चितता का दौर प्रारंभ हो गया है।

एप्पल फोन का निर्माण अधिकांशतया चीन, भारत और वियतनाम में होता है। क्योंकि चीन और वियतनाम में टैरिफ भारत से अधिक लगाया गया है, अत: भारत पर इसका अधिक असर होने की संभावना नहीं है, क्योंकि भारत से अमेरिका में जाने वाले फोन की कीमत इतनी अधिक नहीं बढ़ेगी जितनी चीन और वियतनाम में निर्मित फोन की कीमत बढ़ेगी।

भारत से विभिन्न प्रकार की मछलियों का निर्यात अमेरिका को होता है इसका कुल मूल्य लगभग 20000 करोड रुपए है। इनमें झींगा मछली (प्रॉन) प्रमुख है जिसका हिस्सा लगभग 90% है । ट्रंप टैरिफ के कारण इसमें बहुत कमी आएगी क्योंकि इस व्यवसाय में बढ़ाई गई टैरिफ का भार निर्यातकों को वहन करना पड़ेगा जो लगभग 600 करोड रुपए होता है। इसके विपरीत ब्राजील के लिए टैरिफ 10% ही है, अत: वहां से अमेरिका को आयात करने में सुविधा होगी । इसलिए, भारत का मछली व्यापार बुरी तरह प्रभावित होने की संभावना है । इस व्यापार में लगे हुए लोगों के रोजगार पर भी असर पड़ेगा।

अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाने के कारण भारत से अमेरिका को होने वाले स्टील के निर्यात में कमी आएगी। क्योंकि, अन्य देशों से भी स्टील का निर्यात अमेरिका को नहीं हो पाएगा, अत: अन्य देश अब भारत में स्टील को डंप करने की नीति अपनाएंगे। इसके कारण, भारत के स्टील उद्योग पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है । इस उद्योग में लगे व्यक्तियों का रोजगार भी बहुत हद तक पूरी तरह प्रभावित होगा।

कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि विश्व एक मंदी के दौर की ओर अग्रसर हो रहा है। इसमें नौकरियां कम होगी और कीमतें बढ़ेंगी । इस मंदी के प्रभाव से भारत अपनी नीतियों में सुधार करके स्वयं को कितना बचा पाता है यह भविष्य के गर्भ में है।

ट्रंप द्वारा 1910 के बाद पहली बार इतना अधिक क्रांतिकारी टैरिफ संबंधी निर्णय किया गया है। रेसिप्रोकल टैरिफ को लागू करने की तिथि को ट्रंप 'लिबरेशन डे' के रूप में बता रहे हैं, वहीं कई अर्थशास्त्री इसे 'ट्रेड रिसेशन डे' या 'टैरिफ स्टूपिडिटी डे' के रूप में मनाने की बात कर रहे हैं।

ट्रंप टैरिफ के दुष्प्रभाव से बचने के लिए, फिलहाल तो निम्न दो ही विकल्प दिखाई देते हैं:-

1. अमेरिका द्वारा आयात शुल्क बढ़ाने के कारण अमेरिकी नागरिकों के लिए सभी चीज अत्यंत महंगी हो जाएंगी एवं उसके कारण अमेरिकी नागरिकों का तीव्र विरोध जब ट्रंप के विरुद्ध होगा, तब संभव है उन्हें अपना निर्णय बदलना पड़े। इस प्रकार का घोर विरोध प्रारंभ हो चुका है और पूरे देश में ट्रंप के विरुद्ध प्रदर्शन हो रहे हैं।

2. भारत और अमेरिका परस्पर द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते करें और विभिन्न वस्तुओं के टैरिफ में आपसी सहमति के अनुसार संशोधन करें ताकि भारतीय उद्योग जगत पर इसका विपरीत प्रभाव न पड़े । प्रधानमंत्री मोदी को इस प्रक्रिया के लिए ट्रंप के साथ अपने कथित मित्रता पूर्ण संबंधों का पूरा उपयोग करना पड़ेगा ।

3. वे प्रमुख देश जहां अमेरिका वस्तुओं का निर्यात अधिक होता है, वे भी अपने देश में अमेरिकी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाए अथवा टैरिफ को और बढ़ाए तो अमेरिकी निर्यात पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इस कारण अमेरिका में भी नौकरियां कम हो जाएंगी । इसके फल स्वरुप अमेरिका मंदी के दौर से गुजरेगा और वहां की जनता राष्ट्रपति के विरुद्ध हो जाएगी । जनता के दबाव के कारण ट्रंप को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

फिलहाल तो ऐसा लगता है कि ट्रंप के एक निर्णय ने विश्व की अर्थव्यवस्था को मंदी और अनिश्चितता के दौर में धकेल दिया है।

-अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

ट्रंप के टैरिफ का तूफान

5 ट्रिलियन डॉलर अमेरिकी संपत्ति का नुकसान भारतीय अर्थव्यवस्था के बराबर

अब ज़रूरी है सतर्क रणनीति

सुनील दत्त गोयल

एक समय था जब दुनिया एक साझा नियमों और वैश्विक सहयोग के दौर से गुजर रही थी। वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार के उस युग में ऐसा लगता था कि सभी देश मिलकर आगे बढ़ सकते हैं - एक 'विन-विन' सिस्टम, जहाँ हर किसी को फायदा हो। लेकिन अब वो दौर बीत चुका है। अमेरिका ने हाल ही में 'लिबरेशन डे' पर जिस तरह से नई टैरिफ नीति का ऐलान किया है, वह दुनिया की आर्थिक धारा को ही मोड़ता नज़र आ रहा है। अब यह स्पष्ट हो गया है कि नियमों पर आधारित वैश्विक व्यापार व्यवस्था का अंत हो चुका है - और हम एक नए, कहीं ज़्यादा अनिश्चित और ख़तरनाक युग में प्रवेश कर चुके हैं। चीन और अमेरिका के बीच चल रहा व्यापार युद्ध (Trade War) अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुँच चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाल ही में घोषित नए टैरिफ्स के बाद ना सिर्फ अमेरिकी बाजारों में हाहाकार मचा है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता पर भी गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। इस बार अमेरिका और चीन के बीच आर्थिक टकराव ने जो रूप लिया है, उसका असर पूरी दुनिया पर दिख रहा है - खासतौर पर उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं और बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर।

5 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान: अमेरिकी संपत्ति का विनाश, भारत की GDP के बराबर

ट्रंप द्वारा चीन से आने वाले सेमीकंडक्टर और तकनीकी उत्पादों पर उच्च टैरिफ लगाने के ऐलान के बाद, वॉल स्ट्रीट में तेज़ गिरावट दर्ज की गई। अनुमान के अनुसार, अमेरिकी कंपनियों और निवेशकों को कुल मिलाकर लगभग 5 ट्रिलियन डॉलर (करीब 435 लाख करोड़) का नुकसान हुआ है। यह रकम भारत की पूरी अर्थव्यवस्था (GDP) के बराबर है, जो वैश्विक मंच पर एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था मानी जाती है।

यहां यह देखना अत्यंत आवश्यक है कि भारत जैसा विशाल देश, जहां आज़ादी के लगभग 80 वर्ष पूरे होने को हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए पिछले 11 वर्षों से पूरी मोदी सरकार अथक प्रयास कर रही है। वहीं ट्रंप साहब के एक फैसले ने पूरे विश्व की आर्थिक और व्यापारिक संरचना को झकझोर कर रख दिया है। इस तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि एक गलत नीति निर्णय कैसे किसी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर हिला सकता है।

ट्रंप की आक्रामक नीति और चीन की प्रतिक्रिया

डोनाल्ड ट्रंप पहले ही चीन से आयातित 550 अरब डॉलर के उत्पादों पर 25% से अधिक का टैरिफ लगा चुके हैं। इस नीति का उद्देश्य था अमेरिकी बाजार को 'चीन पर निर्भरता' से मुक्त करना और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना। लेकिन इसके परिणाम अब स्पष्ट रूप से नकारात्मक दिखने लगे हैं। जवाब में चीन ने अमेरिका से आयात होने वाले 16 सेमीकंडक्टर उत्पादों पर 34% तक का टैरिफ लगाया है और कुछ पर प्रतिबंध भी लगाया है। यह कदम सीधे अमेरिकी टेक्नोलॉजी सेक्टर को निशाना बनाता है, जिससे अमेरिकी कंपनियाँ मुश्किल में आ गई हैं।

अब कैसा दिखेगा ये नया दौर?

अमेरिका, जो दशकों तक वैश्विक मुक्त व्यापार प्रणाली का सबसे बड़ा समर्थक था, अब उस पूरी प्रणाली से पीछे हट गया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइज़ेशन (WTO) जैसी संस्थाओं के ज़रिये दुनिया भर में जो नियम-क़ायदे बने थे, उन्हें अब नजरअंदाज किया जा रहा है। अमेरिका अब देश-दर-देश अलग-अलग टैरिफ तय कर रहा है - जिसे वो रिसिप्रोकल टैरिफ कह रहा है। यानी अब यह तय नहीं होगा कि किसी उत्पाद पर कितना शुल्क लगेगा, बल्कि यह देखा जाएगा कि कौन-सा देश अमेरिका को क्या देता है और उसी के आधार पर टैक्स तय होंगे।

एक छोटा लेकिन खतरनाक कदम

शायद किसी एक देश पर लगने वाला 10% टैरिफ ज्यादा बड़ा मुद्दा न लगे। लेकिन असली चिंता इस कदम के पीछे की सोच है। अगर बाकी देश भी यही रवैया अपनाते हैं - कि WTO के नियमों को दरकिनार करके वे भी केवल अपनी शर्तों पर ट्रेड करेंगे - तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन चरमरा सकती है। छोटे और विकासशील देश, जिनकी अर्थव्यवस्था विदेशी व्यापार पर निर्भर है, हाशिए पर चले जाएंगे, उन्हें वैश्विक व्यापार से बाहर किया जा सकता है।

वैश्विक मंदी का खतरा मंडरा रहा है : अमेरिका के इस फैसले के असर से वॉल स्ट्रीट में 5 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की पूंजी उड़ गई - जो भारत की कुल अर्थव्यवस्था (GDP) के बराबर है। सोचिए, एक नीति की घोषणा से अमेरिका ने जितनी संपत्ति गंवाई, वो एक पूरे देश की सालाना आर्थिक गतिविधियों के समान है। ऐसे में ज़रूरत है कि आने वाले फैसलों को बेहद सावधानी से लिया जाए। अगर यही रुख जारी रहा तो वैश्विक व्यापार युद्ध को रोकना मुश्किल होगा। कई देशों ने पहले ही जवाबी टैरिफ की तैयारी शुरू कर दी है यूरोपियन यूनियन, कनाडा, मैक्सिको जैसे देश अब खुद अमेरिकी उत्पादों पर भारी शुल्क लगाने पर विचार कर रहे हैं।

इतिहास की चेतावनी

दुनिया ने इससे पहले ऐसा दौर 1930 के दशक में देखा था, जब व्यापार युद्धों ने आर्थिक मंदी को जन्म दिया, और आगे चलकर यह हालात द्वितीय विश्व युद्ध तक पहुंच गए। अगर अब भी वैश्विक समुदाय ने संयम नहीं दिखाया, तो हालात दोहराए जा सकते हैं।

अंतरराष्ट्रीय नियम टूट रहे हैं

आज की हकीकत यही है कि वैश्विक संस्थाएं कमजोर हो रही हैं। देशों के बीच सहयोग की बजाय प्रतिस्पर्धा और स्वार्थ हावी हो रहा है। बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अब ताक़त और दबाव के बल पर अपने फ़ैसले थोप रही हैं। इस माहौल में छोटे और खुली अर्थव्यवस्था वाले देशों के लिए यह दौर खासा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उन्हें या तो बड़ी शक्तियों की शर्तें माननी होंगी या फिर बाहर कर दिए जाएंगे।

क्या करना होगा अब?

अब देश को न सिर्फ आर्थिक स्तर पर, बल्कि मानसिक रूप से भी तैयार रहना होगा। व्यापार में गिरावट, निवेश में संकोच और कच्चे माल की कीमतों में उथल-पुथल जैसे झटकों के लिए तैयार रहना जरूरी है।

मज़बूत साझेदारियाँ, रणनीतिक निवेश और आंतरिक क्षमता का निर्माण - यही रास्ता है, जिससे कोई देश खुद को इन वैश्विक हलचलों के बीच खड़ा रख सकता है।

निष्कर्ष: ये नया वैश्विक यथार्थ है

ये कोई अस्थायी संकट नहीं है। यह एक नई वैश्विक व्यवस्था की शुरुआत है। ऐसे में यह मानना कि पुराने नियम और सुरक्षा कवच अब भी काम करेंगे, एक भ्रम होगा। जो देश अभी से सतर्क और संगठित हैं, वही इस वैश्विक तूफान में टिक पाएंगे। बाकियों के लिए आने वाला समय और भी कठिन हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि अमेरिका के भीतर ही लोगों में गहरा असंतोष उत्पन्न हो, जो या तो किसी सिविल वॉर (गृहयुद्ध) का रूप ले ले, या वहां मध्यावधि चुनाव की नौबत आ जाए, या फिर ट्रंप की पार्टी कोई और बड़ा फैसला ले ले - जो निश्चित रूप से जोखिम भरा और चौंकाने वाला हो सकता है।

मैं हमेशा से यह कहता आया हूं कि विश्व के किसी भी नेता, राजनेता, अर्थशास्त्री या किसी भी महत्वपूर्ण पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसे संवेदनशील वक्तव्यों से बचना चाहिए। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले यह तुलनात्मक अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है कि उस फैसले का प्रभाव सबसे पहले उनकी राजनीति पर, फिर उनकी जनता पर, और उसके बाद उनकी अर्थव्यवस्था तथा शेयर बाजार के मार्केट कैपिटलाइज़ेशन पर क्या असर डालेगा। हमने भारत में भी यह कई बार देखा है - सरकारें कभी-कभी 1000 से 2000 करोड़ रुपये के टैक्स लगाने की लालसा में 10,000 से 20,000 करोड़ रुपये के मार्केट कैपिटलाइज़ेशन को गंवा देती हैं। नुकसान आम जनता का होता है - सरकारों और नेताओं पर इसका सीधा असर नहीं पड़ता। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैठे हुए उच्च पदों के लोगों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संवेदनशीलता, सहनशीलता, और विवेक का प्रदर्शन करें और हर कदम सोच-समझकर उठाएं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले एक से डेढ़ महीने में इन परिस्थितियों में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। यह भी संभव है कि ट्रंप सरकार को बड़ा रोलबैक करना पड़े। जब पूरा विश्व एक स्वर में जागेगा, तो कोई भी देश - चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो - दबाव में आए बिना नहीं रह पाएगा। और यही तो लोकतंत्र की असली खूबसूरती और ताकत है। धन्यवाद।

-सुनील दत्त गोयल,
महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जयपुर, राजस्थान

बीकानेर : पूर्ण नहरबंदी 25 अप्रैल से संभव, आंशिक नहीं होगी

बीकानेर, (निसं)। इस साल आशिक नहरबंदी की औपचारिक घोषणा नहीं होगी। यद्यपि फरवरी से ही अघोषित आंशिक नहरबंदी जारी है। सूत्रों के मुताबिक इस साल सीधे पूर्ण नहरबंदी होगी जो 25 या 26 अप्रैल से संभावित है। हालांकि इसकी तारीख भी पंजाब ने अभी तक घोषित नहीं की है। दो दशक बाद पहली बार नहरबंदी की तिथि को लेकर पिछले एक महीने से असमंजस की स्थिति है।

पंजाब नहरबंदी की तारीख तय नहीं कर रहा। राजस्थान के अभियंता अपने अनुमान से अलग-अलग तारीख प्रशासन को बता रहे हैं। 26 मार्च से 25 अप्रैल तक आंशिक नहर बंदी होनी थी, लेकिन पंजाब ने इसकी अधिकृत तिथि घोषित नहीं की। हालात इतने विकट हो गए कि अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी समीक्षा के लिए नहरी क्षेत्र का दौरा करना पड़ रहा है। वे आठ और नौ अप्रैल को पंजाब से लेकर राजस्थान तक इंदिरा गांधी नहर का दौरा कर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम जारी हो गया है। माना जा रहा है कि 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री सुबह जयपुर से बठिंडा जाएंगे। यहां से वे हरिके बैराज का निरीक्षण करेंगे। हरिके बैराज वो केंद्र है जहां से पंजाब राजस्थान को सिंचाई और पीना का पानी छोड़ता है। हरिके बैराज से वे

■ आंशिक नहरबंदी घोषित नहीं हो रही और इस दौरान जितना पानी मिलना चाहिए उतना मिल भी नहीं रहा है, पिछले 15 दिन से कटौती चल रही है

लाखों वाली हेड जाएंगे और वहां इंदिरा गांधी नहर में होने वाले मरम्मत कार्यों को देखेंगे। 9 अप्रैल को घग्गर नदी क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे। बाद में हनुमानगढ़ के सर्किट हाउस में प्रशासन और नहरी तंत्र से जुड़े अधिकारियों के साथ नहरबंदी के हालातों की समीक्षा करेंगे। 2006 के बाद वे पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री होंगे जो इंदिरा गांधी नहर का निरीक्षण करेंगे। राजस्थान के अधिकारियों ने 26 मार्च के बाद 5 अप्रैल की तिथि को आंशिक बंदी के लिए अनुमानित तिथि दी थी। 5 अप्रैल को भी पंजाब ने चुप्पी साध ली। अब कहा जा रहा है कि आंशिक नहर बंदी की घोषणा नहीं की जाएगी हालांकि फरवरी से ही अघोषित आंशिक नहर बंदी चल रही है। पानी की कमी को ही कारण माना जा रहा है। आंशिक नहरबंदी में तय पानी दिया जाता है। आंशिक नहरबंदी घोषित नहीं हो रही और इस दौरान जितना पानी मिलना चाहिए उतना मिल भी नहीं रहा। पिछले 15 दिन से कटौती चल रही है। सूत्र बताते हैं कि पंजाब के एक अधिकारी यह कहकर राजस्थान को पूरा पानी नहीं दे रहे कि राजस्थान ने अपने हिस्से का पूरा पानी उपयोग कर लिया है। इसी वजह से पिछले दो सप्ताह से राजस्थान को पूरा पानी नहीं मिल रहा। राजस्थान रोज 3000 क्यूसेक पानी मांग रहा है जबकि उसकी जगह 2000 से ढाई हजार के बीच पानी मिल रहा है। इसमें इंदिरा गांधी नहर और गंगानगर की बाकी दो सिंचाई परियोजनाओं का पानी भी शामिल है, जबकि मिलने वाला सिर्फ पेयजल का पानी है।

अगले तीन दिन तेज गर्मी की संभावना

बीकानेर, (निसं)। बीकानेर में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए तापमान में बढ़ोतरी की आशंका जताते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। सामान्य से अधिक चल रहा पारा रविवार को ही 43.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। पारे में अचानक हुई बढ़ोतरी ने लू के हालात पैदा कर दिए हैं। सोमवार को सुबह आठ बजे भी पारा तीस डिग्री सेल्सियस से ऊपर था। मंगलवार को भी पारा बढ़ सकता है। बुधवार को तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है। हालांकि ये भी सामान्य से अधिक

■ तीन दिन तक लगातार लू रहने की आशंका से लोगों को तेज धूप में सावधानी बरतने की सलाह दी, मंगलवार को पारा बढ़ सकता है, बुधवार को तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है

होगा। तीन दिन तक लगातार लू रहने की आशंका में लोगों को तेज धूप में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अब तक बीकानेर में गर्मी से बचने के लिए कोई खास उपाय नहीं किए गए हैं। पिछले साल नगर निगम ने कोटगेट के पास रेलवे क्रासिंग पर टैंट लगा दिए थे लेकिन इस बार अब तक इस दिशा में निगम की ओर से पहल नहीं हुई है। हालांकि तब ये काम मई में हुआ था, लेकिन इस बार मई जितना पारा अप्रैल में ही पड़ रहा है।

राशिफल मंगलवार 8 अप्रैल, 2025

पंडित अनिल शर्मा

चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, एकादशी तिथि, मंगलेवार, विक्रम संवत 2082, आश्लेष नक्षत्र प्रात: 7:55 तक, शूल योग सायं 6:10 तक, वणिज करण प्रात: 8:37 तक, चन्द्रमा प्रात: 7:55 से सिंह राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मीन, चन्द्रमा-कर्क, मंगल-कर्क, बुध-मीन, गुरू-वृष, शुक्र-मीन, शनि-मीन, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज सर्वार्थ सिद्धि योग सूर्योदय से प्रात: 7:55 तक है। रवियोग प्रात: 7:55 बना रहेगा। कुमार योग प्रात: 7:55 से रात्रि 9:13 तक है। भद्रा प्रात: 8:37 से रात्रि 9:13 तक है। आज कामदा एकादशी, लक्ष्मीकांत दोलोत्सव है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:22 से 10:55 तक, लाभ-अमृत 10:55 से रात्रि 2:02 तक, शुभ 3:36 से 5:10 तक।

राहूकाल: 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 6:14, सूर्यास्त 6:44

मेष
परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। आवश्यक कार्यों के कारण बाहर जाना पड़ सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृष
घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

मिथुन
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों/रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रखें।

कर्क
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

सिंह
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मन:स्थिति में सुधार होगा। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। नवीन कारोबारी अनुबंध प्राप्त होंगे।

कन्या
आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। धन हानि का भय है। अनावश्यक धन खर्च होगा। आज घर-परिवार के कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी।

तुला
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी।

वृश्चिक
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिलेगी।

धनु
व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक पारिवारिक स्थिति ठीक रहेगी।

मकर
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। नवीन कार्यों में परेशानी